[श्री राम विलास पासवान]

कुल लागत 559.89 करोड़ रुपये की थी जो रद्द कर दिया। ज्ञातव्य है कि जिस बिड़ला की कुल पूंजी 1951 में 153 करोड़ रुपया तथा टाटा की 116 करोड़ रुपया थी वह 1975-76 में बढ़ कर 1075 एवं 975 करोड़ क्रमशः हो गई।

सरकार द्वारा उपरोक्त लाइसेंसज दिया जाना जनहित तथा सरकार की घोषित नीतियों के बिल्कुल विपरीत है। अतः सरकार इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

(iv) REPORTED CANCELLATION OF PASSENGER TRAINS ON MANMAD-PURNA AND ADILABAD-PURNA ROUTES.

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड़) : सदर साहब, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर जनता के मसले को यहां पर पेश कर रहा हूं। महाराष्ट्र राज्य के अन्दर कोयले की कमी का एक कारण बता कर रेलवे विभाग ने मनमाड़-पूर्णा, आदिलाबाद-पूर्णा और पूर्णा-परली की पसेंजर रेल गाडियां अभी हाल ही में बन्द की हैं। यह गाडियां बन्द होने से महाराष्ट्र के खास तौर पर मराठवाड़ा प्रभाग की जनता पर इसका बहुत ही बुरा और गम्भीर असर पड़ा है। हजारों गरीब यात्रियों को इस प्रभाग में सफर करना भी मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र और आंध्र के लोगों को भी इसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यह रेलगाड़ियां बन्द होने से लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। यातायात का खर्चा भी बढ़ा है और लोग भी परेशान हैं। उनमें तीव्र असंतोष फैला हुआ है। यह गाड़ियां फौरन शुरू करना बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और इस बारे में वे स्टेटमेंट दें, इसके लिए मैं आपकी ओर से उनसे गुजारिश करता हूं।

सदर साहब, मैंने कल ही मंत्री महोदय से मिल कर इस बारे में निवेदन किया है। आज वे यहां पर हाउस में उपस्थित हैं, मैं आपके द्वारा विनती करूंगा कि मंत्री महोदय यहां पर स्टेटमेण्ट दें।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : वह गाड़ी शुरू करने के आदेश हमने दे दिए हैं।

श्री केशव राव धोंडगे : मैं आपका आभारी हूं।

(v) WORKERS' AGITATION IN HINDUSTAN AERONAUTICS, HYDERABAD

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): Mr. Speaker, Sir, with your permission, under rule 377, I would like to bring to the notice of the Minister of Defence the present state of affairs in Hindustan Aeronautics, Hyderabad. There is, in this enterprise, an Avionic Design Bureau. Air Force personnel who are posted in this Division are on deputation and are, therefore, not under the discipline and control of the management. For example, the management cannot conduct any inquiry into any complaints of harassment by any of these officers.

The present Head of the Department is said to be very arrogant in his behaviour towards the workmen and harasses them. Some time ago the workers went on an agitation in protest. About 100 of them were immediately issued notices of warning. Later the management withdrew the letters and agreed to review the position after three months.

But, within a few days of this, one of the workers was suddenly suspended